गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 312 | दि. 13-03-2019 बुधवार | वि.सं. 2075 | फागण सुद -०७ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

कांग्रेस की वर्किंग कमिटी की मीटिंग के बाद रैली को संबोधित

हमने मसूद अजहर को पकड़ा, आपने छोड़ दिया : राहुल गांधी

राहुल ने मोदी पर हमला बोलते कहा, दो विचारधाराओं की लड़ाई है एक महात्मा गांधी की और दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमिटी की मीटिंग के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने गांधीनगर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों, जवानों, न्यायपालिका और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जिम्मेदार आतंकी मसूद अजहर को कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था लेकिन बीजेपी की सरकार ने मसूद अजहर को हवाई जहाज में बिठाकर पाकिस्तान भेज दिया। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, दो विचारधाराओं की लड़ाई है एक महात्मा गांधी की है और दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी है। आप देखिए कि इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज प्रेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और उसके एकदम बाद जज लोया जी का नाम लेते है। आमतौर पर जनता सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है न्याय के लिए लेकिन आज के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने न्याय मांगते है। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण चालू है। लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और सच्चे मुद्दों की बात सरकार नहीं करती है। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज ४५ साल से ज्यादा बेरोजगारी है। मोदीजी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात करते है लेकिन सच है कि हिंदुस्तान का युवा अलग अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंढते भटक रहा है। दूसरा मुद्दा किसानों का है गुजरात के चुनाव में हमने किसानों की बात की और किसानों ने गुजरात में हमारा पुरा साथ दिया। नरेंद्र मोदीजी ३.५ करोड़ रुपये का १५ लोगो का कर्जा माफ करते हैं लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं करते और उल्टा अरुण जेटली जी कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा, बीमा का पैसा किसान देते हैं लेकिन नुकसान होने पर १५ अमीरों की जेब में पैसा जाता है। हमने तीन प्रदेशों में कर्जमाफी का वादा किया और १० दिन भी नहीं लगे, सिर्फ दो दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। मुझे दुख होता है कि गुजरात के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी भी जरूरत है। राफेल मुद्दे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने मंच से जैसे ही कहा कि चौकीदार, जनता से आवाज आने लगी-चोर है। इसपर राहुल ने कहा, २०१४ के चुनाव में मोदीजी ने कहा था कि चौकीदार बनाओ, पीएम नहीं। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला और लोग चोर बोल रहे है। हर स्टेज से मोदी देशभक्ति की बात करते है। वायुसेना की प्रशंसा करते हैं लेकिन यह नहीं बताते कि वह वायुसेना की जेब से ३० हजार करोड़ चोरी करके पीएम मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाला। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, मसूद अजहर ने पुलवामा में अटैक किया। मैं मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि मसूद अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा। बीजेपी की सरकार ने विशेष हवाई जहाज में बिठाकर और देश का पैसा देकर उसे भेजा। हवाई जहाज में अजीत डोभाल भी एस्कॉर्ट बनकर पाकिस्तान गए। आप देशभक्ति की बात करते है। हमने मसूद अजहर को पकड़ा था लेकिन आपने छोड़ दिया। जिस दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, उसी दिन मोदीजी ने अपने दोस्त के नाम देश के पांच एयरपोर्ट कर दिए।

१५ लाख खातें में आने थे, वे कहां है

भविष्य चुनने जा रहे हैं आप, जागरूक बनना सच्ची देशभक्ति

प्रियंका ने कहा यह देश आपका है, जो लोग बड़ी बातें करते उनसे पूछिए १५ लाख खातें में आने थे, वे कहां है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। गांधीनगर में करीब १० मिनट के अपने पहले और नपे-तुले संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी, प्रेम और अहिंसा की बात करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह देश आपका है, जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनसे पूछिए कि जो १५ लाख रुपये आपके खातें में आने थे, वे कहां है। करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले दो महीनों में फिजूल के मुद्दे उठाए जाएंगे, ऐसे में आपको जागरूक होना है क्योंकि इस चुनाव के जरिए आप अपना भविष्य चुनने जा रहे है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक मंगलवार को अहमदाबाद में हुई, जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रियंका ने कहा, मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है लेकिन मन में सोचा था कि शायद भाषण देने की जरूरत न पड़े। मैं भाषण नहीं देती हूं आपसे दो शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पहली बार गुजरात आई हूं और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई, जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। उन्होंने कहा, वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए मेरे आंसू ा गए। मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव पड़ी है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है लेकिन आज जो कुछ देश में हो रहा है, उससे दुख होता है। प्रियंका ने कहा, मैं दिल से आपसे कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बनें। आपकी जागरूकता एक हथियार है। आपका वोट एक हथियार है लेकिन यह ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को दुख नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहूत गहराई से सोचना पड़ेगा कि यह चुनाव क्या है। प्रियंका ने कहा कि इस चुनाव के जरिए आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। ऐसे में फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। आपके लिए मुद्दे वहीं उठने चाहिए जिसमें आपका हित है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी, वे सुरक्षित कैसे रहेंगी। किसानों के लिए क्या जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं। आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। इस बार सोच-समझकर ही निर्णय लें। उन्होंने कहा कि जो आपके साथ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं। उनसे पूछिए कि दो करोड़ रोजगार कहां हैं। उनसे पूछिए जो १५ लाख आपके खाते में आने थे, वे कहां है। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, उन्हें पांच साल में किसने पूछा है। सही सवाल कीजिए क्योंकि आने वाले दो महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे।

महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा

नेता राधाकृष्ण का बेटा सुजय पाटील बीजेपी में शामिल हुए

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की ५८ साल बाद गुजरात में अहम बैठक चल रही है और इस बीच महाराष्ट्र में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील के बेटे सुजय विखे पाटील मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजय ने पार्टी नेताओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह का इसके लिए शुक्रिया अदा करते है। सुजय ने कहा, मैंने यह फैसला अपने पिता के खिलाफ लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे पैरंट्स इस फैसले का कितनाॉ समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में मैं अपना सबकुछ झोंक दुगा ताकि मेरे माता-पिता गर्व महसूस कर सकें। सीएम और बीजेपी विधायकों ने मेरे इस फैसले का पूरा समर्थन किया। बाद में देवेंद्र फडणनवीस ने इस मौके पर कहा, राज्य इकाई ने सुजय ा विखे पाटील का नाम लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेज दिया है। हमें उम्मीद है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड उनकी उम्मीदवारी को मंजूर कर लेगा। सुजय विखे पाटील के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अहमदनगर से कई अन्य प्रमुख नेता और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते है। मौजूदा संकेतों के अनुसार, सुजय विखे पाटील को शायद अहमदनगर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़वाया जा सकता है। अहमदनगर को प्रसिद्ध विखे-पाटील परिवार का गढ़ माना जाता है और सुजय इस परिवार की चौथी पीढ़ी है। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने सुजय से हाल ही में मुलाकात कर बीजेपी में उनके शामिल होने पर चर्चा की थी।

मोदी और शाह का शुक्रिया अदा करते हुए सुजय ने कहा, मैंने यह फैसला अपने पिता के खिलाफ लिया

पाक- चीन से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति, अब दुश्मन नहीं खोज पाएंगे फाइटर प्लेन

(जी.एन.एस.) नई दिल्ली। दुश्मन के मिसाइल और बमबारी से एयर बेस को बचाने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है। सरकार ने वायु सेना को चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक लगभग 110 ठिकाने बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 110 ठिकानों के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो फाइटर प्लेन को दुश्मन की मिसाइल और बॉमिंग से बचाएगी, जिसे ब्लास्ट पेन भी कहते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट का खर्च 5000 करोड़ से ज्???यादा होगा और ब्लास्ट पेन एयर बेस की तर्ज पर बनाए जाएंगे। इस कदम से वायुसेना अपने फ्रंटलाइन प्लेन को बिना जमीनी नुकसान की चिंता के फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर सकेगी।

अभी तक इस सुविधा के बिना वायुसेना आपरेशन के दौरान फ्रंटलाइन प्लेन्स को पाकिस्तान सीमा के पास कुछ चुनिंदा स्थानों पर तैनात कर पाती थी। 26 फरवरी के एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया था। 1965 के युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना अपने कई विमान खोए थे, तब से एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए वायुसेना ब्लास्ट प्लेन बना रही है। इन 100 ठिकानों में मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएंगी जिससे यह दुश्मन के बड़े हमले से बचाएगी। इस रणनीति से भारत पाकिस्तान और चीन से निपटने में आसनी होगी। वर्तमान हालात को देखकर यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

भाजपा मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक टिकट बचाने में जुटे सांसद, नए दावेदारों ने भी लगाया जोर

(जी.एन.एस.) लखनऊ, जेएनएन। लोकसभा के पहले चरण का नामांकन 18 अप्रैल से ही शुरू होना है लेकिन, सत्ताधारी भाजपा ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के 68 सांसद हैं और इनमें कई टिकट कटने की आशंका से घबराए हुए हैं। ऐसे सांसद अपना टिकट बचाने में ताकत लगा रहे हैं, वहीं नए दावेदार भी क्षेत्रीय संगठन, प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक परिक्रमा में जुट गए हैं। इस बीच दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हो रहे पूर्व सांसदों के चलते भी मौजूदा सांसदों की धड़कन बढ़ गई है। भाजपा मुख्यालय में इन दिनों सांसद खूब सक्रिय देखे जा रहे हैं। अवध क्षेत्र की एक महिला सांसद ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल समेत कई नेताओं ने मुलाकात कर आशीर्वाद मांगा है। ऐसे ही कानपुर क्षेत्र के एक सांसद भी आश्वस्त होते देखे गए तो प्रयागराज में चुनाव लडने के लिए योगी सरकार के मंत्री को भी मुख्यालय में संपर्क साधते देखा गया। बिजनौर जिले के नगीना के पूर्व सांसद यशवीर धोबी ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की तो वहां के मौजूदा सांसद के एक प्रभावी समर्थक टोह लेने आ गए। दरअसल, नगीना के सांसद डॉ. यशवंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई गंभीर सवाल उठाए और दलित हितों के मुद्दे पर विद्रोही तेवर दिखाए थे। हालांकि बाद में वह भाजपा के कार्यक्रमों में सक्रिय हो गए लेकिन, जब डॉ. यशवीर भाजपा में शामिल हुए तो उनके समर्थकों की धड़कन बढ़ गई। घोसी क्षेत्र के सांसद हरिनारायण राजभर भी अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए संपर्क साध रहे हैं। उधर, सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने घोसी सीट पर दावा ठोंक दिया है। घोसी के कई अन्य दावेदारों ने भी भाजपा मुख्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं तक अपनी अर्जी पहुंचाई है। ऐसे ही प्रदेश के विभिन्न अंचलों से दावेदार और उनके समर्थक टिकट के लिए चौतरफा अपना जुगाड़ लगा रहे हैं।

संपादकिय

राजनीतिक शरारत-जब नवरात्र में चुनाव में हो सकते हैं, तो फिर रमजान के महीने में क्यों नहीं?

निर्वाचन आयोग ने बेतुकी आपत्ति उठाने वालों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि यह नहीं हो सकता कि रमजान के दौरान मतदान हो ही न। यह आपत्ति एक किस्म की राजनीतिक शरारत ही है कि रमजान के महीने में आम चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? यह मानने के अच्छे–भले कारण हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से आम चुनाव की घोषणा होते ही कुछ राजनीतिक दलों ने खुद को मुस्लिम समुदाय का हितचिंतक जताने के लिए ही यह कहा कि रमजान के दौरान चुनाव कराना ठीक नहीं। रमजान का माह मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक वैसा ही पावन कालखंड होता है जैसे हिंदू समुदाय के लिए नवरात्र। अब अगर नवरात्र में चुनाव में हो सकते हैं तो फिर रमजान में क्यों नहीं हो सकते? यह सही है कि रमजान में मुस्लिम एक खास दिनचर्या का निर्वाह करते हैं, लेकिन इस दौरान वे अपने सारे काम अन्य दिनों की तरह ही करते हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह मान रखा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम अपना काम–धंधा छो?कर घर बैठ जाते हैं? एमआइएम के नेता असदुद्दीन औवेसी ने यह जवाबी सवाल दागकर एक तरह से इन राजनीतिक दलों को शर्मिंदा ही किया कि क्या रमजान के दौरान मुसलमान काम नहीं करते? समझना कठिन है कि चंद राजनीतिक दलों की तरह से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि रमजान के कारण मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी आ सकती है? कम से कम उन्हें तो यह सामान्य सी जानकारी होनी ही चाहिए कि रमजान का मतलब दैनिक जीवनचर्या को रोक देना नहीं होता। रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने पर आपत्ति का तब कोई मूल्य हो सकता था जब ईद या अन्य किसी पर्व के दिन मतदान की तिथि घोषित की जाती। आम तौर पर निर्वाचन आयोग इसका ख्याल रखता है कि किसी ब? पर्व के दिन मतदान न हो। अतीत में उसने किसी क्षेत्रीय पर्व–महोत्सव के दौरान होने वाले मतदान को टाला भी है। इस बार भी उसने रमजान को ध्यान में रखते हुए इस दौरान किसी शुक्रवार को मतदान की तिथि घोषित नहीं की। राजनीतिक दलों को यह पता होना चाहिए कि रमजान के दौरान चुनाव अतीत में भी होते रहे हैं और इसके पहले कभी यह सुनने को नहीं मिला कि रमजान में चुनाव नहीं होने चाहिए। बहुत दिन नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा का उपचुनाव रमजान के समय ही हुआ था। क्या तब मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने में दिक्कत पेश आई थी या फिर ऐसा कुछ सामने आया था कि रमजान में मतदान होने के कारण किसी दल विशेष को चुनावी नफा या नुकसान हुआ? रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर आपत्ति उठाने वालों ने अपनी सांप्रदायिक सोच का ही परिचय दिया है। इसके जरिये उनका एकमात्र मकसद खुद को मुस्लिम समुदाय की परवाह करने वाला दिखाना और इसी बहाने चुनावी लाभ लेना ही रहा होगा। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने बेतुकी आपत्ति उठाने वालों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि यह नहीं हो सकता कि रमजान के दौरान मतदान हो ही न। बेहतर होगा कि मुस्लिम समुदाय भी इस पर विचार करे कि रमजान के दौरान चुनाव का सवाल उठाने वाले उसके हितैषी हैं या फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले?

घर–परिवार का अर्थशास्त्र-स्वतंत्र आय हासिल करने से महिला सबल और स्वस्थ्य रहती हैं

महिला और पुरुष का भेद पुरातन है। पहले जीव एक सेल के गैमेट (युग्मक) होते थे। ये एकलिंगीय और केवल एक कोशिका से बने होते थे। इनमें नर और मादा नहीं होते थे। फिर भी दो गैमेट के संयोग से नए गैमेटों का सृजन होता था। बडे गैमेट अपनी जगह स्थिर रहने लगे, जबकि छोटे गैमेट तेजी से इधर–उधर चलकर उनके साथ जुटने लगे। ये बडे गैमेट समयक्रम में मादा बने और छोटे गैमेट नर बने। आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक दृ?ता ज्यादा होती है। शायद यही कारण है कि अमेरिका में महिलाओं की औसत आयु 80 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु मात्र 70 वर्ष है। महिलाएं छोटे बच्चों को इसलिए आसानी से पाल पाती हैं, क्योंकि वे उनसे अचेतन वार्तालाप कर सकती हैं और बातें करते रहना उनके लिए आसान होता है। गणित आदि तार्किक विचारों और संकल्प की पूर्ति में पुरुष ज्यादा निपुण होते हैं। जैसे–जैसे जीवों का विकास होता गया वैसे–वैसे नर और मादा के अंतर बडते गए और आज यह अंतर मनोवैज्ञानिक भी हो गया है। हम यह मान सकते हैं कि जिस प्रकार बीते अरबों वर्षों में यह अंतर ब?ता गया है, आगे भी यह बडता ही जाएगा। 21वीं सदी के परिवार की संरचना को समझने का दूसरा आधार नई तकनीकें हैं। बिजली से जलने वाले बल्ब एवं बिजली से ही चलने वाली मिक्सी और वाशिंग मशीन, पाइप से आने वाला पानी, गैस से चलने वाले स्टोव आदि उपकरणों से घरेलू कार्य सरल हो गए हैं। पहले परिवार चलाने के लिए एक व्यक्ति को पूरा समय इन कार्यों को करने के लिए देना पडता था। अब ये कार्य घंटे दो घंटे में संपन्न हो जाते हैं। इसलिए महिला के लिए अब पर्याप्त समय दूसरे कार्यों के लिए उपलब्ध हो गया है। 21वीं सदी के परिवार की संरचना हमें इन दोनों कारकों के बीच खोजनी है। एक यह कि महिला और पुरुष के बीच अंतर ब?ता जाएगा और दूसरा यह कि गृह कार्य के लिए एक व्यक्ति को अपना पूर्ण समय देना अब जरूरी नहीं रह गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज के प्रचलित परिवार के नए ढांचे के सुझावों का आकलन कर सकते हैं। एक सुझाव है कि महिला और पुरुष गृह कार्य में बराबर का योगदान करें जैसे भोजन पकाने अथवा कपडा धोने के लिए। यह महिला और पुरुष अथवा नर और मादा के बीच बडते अंतर के ऊपर बताए सिद्धांत के विरुद्ध बैठता है। अरबों वर्षों की जीवों की यात्रा बताती है की नर और मादा का अंतर बडता गया है। एक कोशिका वाले गैमेट में केवल आकार या वजन का अंतर था। पौधों में केवल फूल के आकार में अंतर होता है। मनुष्य में मनोवैज्ञानिक अंतर भी हो गया है। आने वाले समय में यह अंतर बडेगा। इसलिए पुरुष और स्त्री के कार्यों में भी अंतर बडेगा। दोनों घर का बराबर काम करें, यह नहीं चलेगा। दूसरा सुझाव है कि महिला अर्थोपार्जन करे। तमाम अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि स्वतंत्र आय हासिल करने से महिला का सबलीकरण होता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, लेकिन दूसरे अध्ययनों से यह भी पता लगता है कि पूर्णकालिक कार्य करने वाली महिला पर दोहरा वजन आ प?ता है। कनाडा के परिवारों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि पूर्णकालिक कार्य करने वाली महिलाएं 25 मिनट कम सो पाती हैं। इसलिए यह सुझाव गृह कार्य से मुक्ति के ऊपर बताए गए सिद्धांत के विरुद्ध बैठता है। इस सुझाव में महिला को गृह कार्य तो कम करना प?ता है, लेकिन कम गृह कार्य को पूर्णकालिक कमाई के साथ करने से उसके ऊपर कुल कार्य का वजन पडता है। इसलिए ये दोनों सुझाव मानव विकास की मूल धारा के विपरीत हैं और ये लंबे समय तक चल पाएंगे ऐसा नहीं लगता है। प्रश्न है कि इन सुझावों के असफल होने के बावजूद इन्हें क्यों ब?ाया जा रहा है। ऐसा समझ आता है कि महिला और पुरुष के बीच बराबरी की बात छे?कर समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता से हमारा ध्यान हटा दिया जा रहा है। जिस प्रकार एक चतुर बंदर ने दो मूर्ख बिल्लियों की ल?ई के बीच उनकी रोटी चट कर ली थी अथवा जिस प्रकार एक चतुर उद्यमी दो ट्रेड यूनियनों को आपस में ल?ाकर लाभ कमाता है उसी प्रकार महिला और पुरुष को घर के अंदर बराबरी का मंत्र देकर समाज में ब?ती आर्थिक असमानता से हमारा ध्यान हटा दिया जा रहा है। हर वर्ष समाचार छपते हैं कि देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से ब? रही है, लेकिन इस ब?ती असमानता के ऊपर तनिक भी सामाजिक हलचल नहीं होती, क्योंकि समाज ने परिवार के अंदर महिला और पुरुष के बीच बराबरी हासिल करने को प्राथमिक बना दिया है और सामाज में गरीब और अमीर के बीच बडती असमानता को छिपा दिया है ताकि अमीरों की ब?ती आय से समाज का ध्यान हट जाए। ऊपर दिए गए दोनों कारकों को देखते हुए आने वाले समय में परिवार का रूप दूसरा बनाया जा सकता है। वह यह कि महिला को पार्ट टाइम कार्य के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। साथ में उसके द्वारा किए गए गृह कार्य को सम्मानित किया जाए। ऐसा करने से महिला और पुरुष का जो बडता अंतर है वह उपयोगी सिद्ध होगा। महिला की बच्चों को पलने की जो शक्ति है उसका समाज को भरपूर लाभ मिलेगा। महिला बच्चों के पालन में उनकी मनोवैज्ञानिक परवरिश कर सकेगी। साथ–साथ पार्ट टाइम कार्य करने से महिला का आर्थिक सबलीकरण भी होगा। उसके ऊपर दोहरा बोझ भी नहीं आएगा। मेरे एक जानकर मित्र की पत्नी ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करती हैं। बच्चे पैदा होने के दो साल बाद तक उन्होंने सप्ताह में केवल दो दिन कार्य किया, शेष पांच दिन उन्होंने अपने बच्चों और घर को समर्पित किया। ऐसा करने से उनका आर्थिक सबलीकरण भी हुआ और उन पर कार्य का दोहरा बोझ भी नहीं प?ा। हमें इस पर विचार करना होगा कि महिलाओं के लिए सुलभ समय और दिन के कार्य के अवसर प्रदान करें। जैसे गार्ड का कार्य आठ घंटे की जगह चार घंटे की शिफ्टों में किया जा सकता है अथवा महिलाओं को सप्ताह में दो या तीन दिन कार्य करने और इतने ही दिन अवकाश लेने की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन से महिला और पुरुष का जो मनोवैज्ञानिक अंतर है उसका समाज को लाभ मिलेगा और नई तकनीकों से महिला का वास्तविक सबलीकरण होगा न कि उसे दोहरे बोझ से लाद दिया जाएगा।

जानें, आखिर क्या है सुरक्षा परिषद का Chapter Resolution, जिससे डरता है पाकिस्तान

(जी.एन.एस.) भारत को दृता से पाकिस्तान से यह मांग करनी चाहिए कि आतंकियों के खिलाफ नौटंकी बंद कर असली कार्रवाई करे। साथ ही अलग–अलग देश और अंतरराष्ट्रीय समूह भी उस कार्रवाई की निगरानी करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ प्रस्ताव को अपनाने के लिए सक्षम है, जिसका सभी सदस्य देशों को अनुपालन करना होता है। इन्हें आमतौर पर अध्याय 7 प्रस्ताव कहा जाता है। यूएनएससी ने 3 प्रस्तावों को अपनाया है, जो आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को एक सूची में रखने में सक्षम बनाते हैं। चूंकि पहले प्रस्ताव की संख्या 1267 थी, इसलिए इन सूचियों को 1267 सूचियों के रूप में जाना जाता है। जब एक आतंकी या आतंकी संगठन को 1267 सूची में डाल दिया जाता है, तो सभी सदस्य देश उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं। हाफिज सईद, जकी–उर–रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को इस सूची में शामिल किया गया है। यह तीनों आतंकवादी भारत में भयानक आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार हैं। जो आतंकी संगठन सूचीबद्ध हैं, उनमें जैश–ए–मुहम्मद और लश्कर–ए– तैयबा शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2002 में इन संगठनों पर मुकदमा चलाया, लेकिन उन्हें अलग–अलग नामों से जारी रखने की अनुमति दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हितों को ब?ावा देने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सभी पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हां, हाफिज सईद को पहले भी हिरासत में रखा गया है लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद उसे आजाद कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 26/11 मुंबई हमले के मामले में लखवी जेल में बंद था। जेल में रहते हुए वह एक बच्चे का पिता बना और बाद में उसे जमानत दे दी गई। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने फिर से कार्रवाई की है। उसने मसूद अजहर से जुडे लोगों को हिरासत में लिया है और जमात–उद–दावा और फलाह–ए–इंसानियत पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये संगठन लश्कर–ए–तैयबा के सहयोगी हैं। भारत को यह दृ?ता से मांग करनी चाहिए कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अस्थायी नहीं बल्कि वास्तविक हो और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इनकी निगरानी करे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के माध्यम से भी पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा रहा है। एफएटीएफ भारत सहित 37 सदस्यों वाला एक अंतर–सरकारी संगठन है, जो आतंकवादी वित्तपोषण को नियंत्रित करता है। एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान की निगरानी जारी है, क्योंकि उसने सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले फंड को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं जो आतंकवादी वित्तपोषण को नियंत्रित करता है। एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान की निगरानी जारी है, क्योंकि उसने सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले फंड को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। हाफिज सईद, जकी–उर–रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को इस सूची में शामिल किया गया है। भारत को यह दृ?ता से मांग करनी चाहिए कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अस्थायी नहीं बल्कि वास्तविक हो और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इनकी निगरानी करे। इनमें जैशए–मुहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा शामिल हैं। दाऊद इब्राहिम को इस सूची में शामिल किया गया है। यह तीनों आतंकवादी भारत में भयानक आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार हैं। जो आतंकी संगठन सूचीबद्ध हैं, उनमें जैश–ए–मुहम्मद और लश्कर–ए– तैयबा शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2002 में इन संगठनों पर मुकदमा चलाया, लेकिन उन्हें अलग–अलग नामों से जारी रखने की अनुमति दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हितों को बडावा देने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सभी पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हां, हाफिज सईद को पहले भी हिरासत में रखा गया है लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद उसे आजाद कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 26/11 मुंबई हमले के मामले में लखवी जेल में बंद था। जेल में रहते हुए वह एक बच्चे का पिता बना और बाद में उसे जमानत दे दी गई। इस निगरानी के साथ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को धन जुटाने में नानी याद आ रही है। यदि पाकिस्तान एफएटीएफ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो इसे काली सूची में भी डाला जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वैश्विक बैंकों से इसका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन बहुत महंगा हो जाएगा, इसके साथ व्यापार करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। जिससे पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरा जाएगा और चीन पर निर्भरता और अधिक बडेगी। भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद जारी रखना होगा। लेकिन अंत में भारत को पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ खुद ही युद्ध लडना होगा।

ये है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असली रक्तबीज

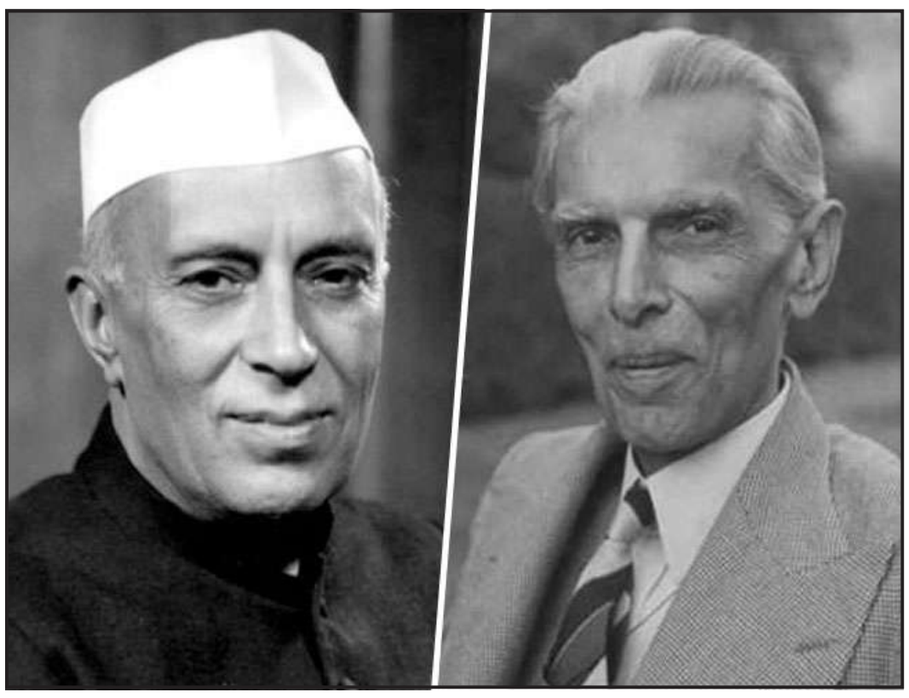

(जी.एन.एस.) कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 72 वर्षों से चली आ रही तनातनी का केंद्र है। मगर हकीकत यह कि कश्मीर भारत–पाक तनाव का वास्तव में जरिया नहीं है। इसके मूल में है 1947 में हुआ भारत का सांप्रदायिक विभाजन। कश्मीर समस्या की जडें वास्तव में इसी सांप्रदायिक विभाजन में छिपी हैं जो तनाव का रक्तबीज है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को 'अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन' कहता है। जबकि भारत के लिए कश्मीर उस धारणा का प्रतीक है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत के लिए उसका पार्टीशन एक बडी भूल थी। विभाजित भारत ने मुस्लिम बहुल व एक रजवाडे द्वारा शासित कश्मीर का जब वरण किया, तब वह एक परिस्थितिजन्य घटना थी। बाद में भारत ने कश्मीर पर यदि अपना वर्चस्व स्थापित भी किया तो उसके पीछे मंतव्य कहीं न कहीं उसके विगत के सांप्रदायिक विभाजन को नकारे जाने का ही प्रतीक था। इसके साथ ही यह इस बात का भी द्योतक था कि भारत मुस्लिम संप्रदायवादियों द्वारा विभाजित किए जाने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके हर कोने में मुस्लिम धमार्वलंबियों की अच्छी खासी आबादी रहती है जो कि संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी के ही करीब बराबर है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में चल रहा मौजूदा सांप्रदायिक अलगाववाद कोई नए सिरे से उत्पन्न हुआ मसला नहीं है, बल्कि यह मसला तो पाकिस्तान के विभाजन का ही रक्तबीज है जो अभी कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने की वजह से या तो भारत से अलग होने की बात कर रहा है या फिर इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के करीब जाने की कवायद कर रहा है। आम पाकिस्तानी भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते. इसमें जो कश्मीरी एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ अपनी अस्मिता की सुरक्षा देखता है, उनकी समझदारी को सलाम। परंतु सवाल यह है कि इस अशांत रियासत में कश्मीर में पहले से जुडा हुआ नाम जम्मू है, आखिर वह क्यों नहीं अलग होने की बात कर रहा है? जाहिर है इस अलगाववाद की जडें बांग्लादेश की तरह सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सांपद्रायिक हैं। पाकिस्तान के नजरिये से देखें तो वह समझता है कि उन्होंने 1971 में बंगाल को इसीलिए खोया, क्योंकि वह सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर पंजाबी बहुल पाकिस्तान के मातहत नहीं आ पा रहा था, जबकि उसकी सीमा से लगे मुस्लिम बहुल कश्मीर हासिल करने के लिए उसे हर तरह की कुर्बानी मंजूर है देखा जाए तो संवैधानिक व वैधानिक और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर पर पाकिस्तान का आधिपत्य नहीं बनता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का तो भारत से पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन किया हुआ है। क्योंकि उसने कबायलियों द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर से अपने आप को अलग नहीं किया जो कि उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक करना था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अति आत्मविश्वास में कश्मीर को लेकर भारत पर तीन बार हमले किए, पर तीनों में उसे हार का सामना करना पडा। ऐसे में पाकिस्तान अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि कश्मीर पर उसकी जिहाद की नीति यानी छद्म युद्ध की नीति उसके लिए माकूल बैठती है, जिसके जरिये ही वह अक्टूबर 1947 में कश्मीर का करीब 40 फीसद हिस्सा हासिल करने में कामयाब हुआ था और इसी दौरान वह इसका पूर्वी हिस्सा 'अक्साई चिन', चीन को देकर उससे सामरिक संपर्क जो?ने का मकसद हासिल किया। वर्ष 1999 में हुआ कारगिल अतिक्रमण 1947 के छद्म युद्ध की ही दूसरी कडी थी, जिसमें अपने क्षेत्र को दोबारा हासिल करने के लिए भारत को युद्ध करना पडा। अभी पाकिस्तानी हुक्मरानों में यह विश्वास पनप चुका है कि कश्मीर का लक्ष्य उन्हें उनकी सेना के जरिये नहीं, बल्कि उसकी छाया में पल व चल रहे आतंकी गुट ही हासिल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अभिनंदन की वापसी को लेकर इमरान खान की अभी भारत में भी तारीफ हुई, जबकि प्रश्न यह है कि आखिर भारत के नजरिये से उन आतंकी गुटों पर नकेल कसने को लेकर उन्होंने आखिर ऐसी कौन सी पहल दिखाई? वह पाकिस्तान जो विगत में भारत के मृत सैनिकों के शव क्षत–विक्षत करके लौटाता था, उसने यदि अमेरिका के दबाव में या आक्रामक भारत पर अपनी नैतिक बडत हासिल करने के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को लौटाया भी है तो यह उसके जरिये भारत की सैन्य आक्रामकता को तात्कालिक रूप से कम करने का प्रयास भर ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस द्वंद्व का समाधान हो, इसके लिए आखिरी रास्ता इसके तह में जाना ही बनता है। बाद में भारत ने कश्मीर पर यदि अपना वर्चस्व स्थापित भी किया तो उसके पीछे मंतव्य कहीं न कहीं उसके विगत के सांप्रदायिक विभाजन को नकारे जाने का ही प्रतीक था। इसके साथ ही यह इस बात का भी द्योतक था कि भारत मुस्लिम संप्रदायवादियों द्वारा विभाजित किए जाने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके हर कोने में मुस्लिम धमार्वलंबियों की अच्छी खासी आबादी रहती है जो कि संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी के ही करीब बराबर है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में चल रहा मौजूदा सांप्रदायिक अलगाववाद कोई नए सिरे से उत्पन्न हुआ मसला नहीं है, बल्कि यह मसला तो पाकिस्तान के विभाजन का ही रक्तबीज है जो अभी कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने की वजह से या तो भारत से अलग होने की बात कर रहा है या फिर इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के करीब जाने की कवायद कर रहा है। आम पाकिस्तानी भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते. इसमें जो कश्मीरी एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ अपनी अस्मिता की सुरक्षा देखता है, उनकी समझदारी को सलाम। परंतु सवाल यह है कि इस अशांत रियासत में कश्मीर में पहले से जुडा हुआ नाम जम्मू है, आखिर वह क्यों नहीं अलग होने की बात कर रहा है? जाहिर है इस अलगाववाद की जडें बांग्लादेश की तरह सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सांपद्रायिक हैं। पाकिस्तान के नजरिये से देखें तो वह समझता है कि उन्होंने 1971 में बंगाल को इसीलिए खोया, क्योंकि वह सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर पंजाबी बहुल पाकिस्तान के मातहत नहीं आ पा रहा था, जबकि उसकी सीमा से लगे मुस्लिम बहुल कश्मीर हासिल करने के लिए उसे हर तरह की कुर्बानी मंजूर है देखा जाए तो संवैधानिक व वैधानिक और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर पर पाकिस्तान का आधिपत्य नहीं बनता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का तो भारत से पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन किया हुआ है। क्योंकि उसने कबायलियों द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर से अपने आप को अलग नहीं किया जो कि उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक करना था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अति आत्मविश्वास में कश्मीर को लेकर भारत पर तीन बार हमले किए, पर तीनों में उसे हार का सामना करना पडा। ऐसे में पाकिस्तान अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि कश्मीर पर उसकी जिहाद की नीति यानी छद्म युद्ध की नीति उसके लिए माकूल बैठती है, जिसके जरिये ही वह अक्टूबर 1947 में कश्मीर का करीब 40 फीसद हिस्सा हासिल करने में कामयाब हुआ था और इसी दौरान वह इसका पूर्वी हिस्सा 'अक्साई चिन', चीन को देकर उससे सामरिक संपर्क जो?ने का मकसद हासिल किया। वर्ष 1999 में हुआ कारगिल अतिक्रमण 1947 के छद्म युद्ध की ही दूसरी कडी थी, जिसमें अपने क्षेत्र को दोबारा हासिल करने के लिए भारत को युद्ध करना पडा। अभी पाकिस्तानी हुक्मरानों में यह विश्वास पनप चुका है कि कश्मीर का लक्ष्य उन्हें उनकी सेना के जरिये नहीं, बल्कि उसकी छाया में पल व चल रहे आतंकी गुट ही हासिल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अभिनंदन की वापसी को लेकर इमरान खान की अभी भारत में भी तारीफ हुई, जबकि प्रश्न यह है कि आखिर भारत के नजरिये से उन आतंकी गुटों पर नकेल कसने को लेकर उन्होंने आखिर ऐसी कौन सी पहल दिखाई? वह पाकिस्तान जो विगत में भारत के मृत सैनिकों के शव क्षत–विक्षत करके लौटाता था, उसने यदि अमेरिका के दबाव में या आक्रामक भारत पर अपनी नैतिक बडत हासिल करने के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को लौटाया भी है तो यह उसके जरिये भारत की सैन्य आक्रामकता को तात्कालिक रूप से कम करने का प्रयास भर ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस द्वंद्व का समाधान हो, इसके लिए आखिरी रास्ता इसके तह में जाना ही बनता है। बाद में भारत ने कश्मीर पर यदि अपना वर्चस्व स्थापित भी किया तो उसके पीछे मंतव्य कहीं न कहीं उसके विगत के सांप्रदायिक विभाजन को नकारे जाने का ही प्रतीक था। इसके साथ ही यह इस बात का भी द्योतक था कि भारत मुस्लिम संप्रदायवादियों द्वारा विभाजित किए जाने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके हर कोने में मुस्लिम धमार्वलंबियों की अच्छी खासी आबादी रहती है जो कि संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी के ही करीब बराबर है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में चल रहा मौजूदा सांप्रदायिक अलगाववाद कोई नए सिरे से उत्पन्न हुआ मसला नहीं है, बल्कि यह मसला तो पाकिस्तान के विभाजन का ही रक्तबीज है जो अभी कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने की वजह से या तो भारत से अलग होने की बात कर रहा है या फिर इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के करीब जाने की कवायद कर रहा है। आम पाकिस्तानी भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते. इसमें जो कश्मीरी एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ अपनी अस्मिता की सुरक्षा देखता है, उनकी समझदारी को सलाम। परंतु सवाल यह है कि इस अशांत रियासत में कश्मीर में पहले से जुडा हुआ नाम जम्मू है, आखिर वह क्यों नहीं अलग होने की बात कर रहा है? जाहिर है इस अलगाववाद की जडें बांग्लादेश की तरह सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सांपद्रायिक हैं। पाकिस्तान के नजरिये से देखें तो वह समझता है कि उन्होंने 1971 में बंगाल को इसीलिए खोया, क्योंकि वह सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर पंजाबी बहुल पाकिस्तान के मातहत नहीं आ पा रहा था, जबकि उसकी सीमा से लगे मुस्लिम बहुल कश्मीर हासिल करने के लिए उसे हर तरह की कुर्बानी मंजूर है देखा जाए तो संवैधानिक व वैधानिक और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर पर पाकिस्तान का आधिपत्य नहीं बनता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का तो भारत से पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन किया हुआ है। क्योंकि उसने कबायलियों द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर से अपने आप को अलग नहीं किया जो कि उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक करना था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अति आत्मविश्वास में कश्मीर को लेकर भारत पर तीन बार हमले किए, पर तीनों में उसे हार का सामना करना पडा। ऐसे में पाकिस्तान अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि कश्मीर पर उसकी जिहाद की नीति यानी छद्म युद्ध की नीति उसके लिए माकूल बैठती है, बल्कि विभाजन है। यह बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और अब भारत के भी कुछेक कट्टरपंथियों को नागवार लगेगी। परंतु यह बात सोलह आने सच है कि इसके बीज ब्रिटिश बोकर गए और नतीजा हमारे सैनिकों को बलिदान देकर भुगतना प?ता है। देखा जाए तो पाकिस्तान का निर्माण ही अनैतिक था और इसीलिए यह एक असफल देश है।

सिर्फ पटाखों पर बैन क्यों : सुप्रीम कोर्ट

ऑटोमोबाइल्स से कहीं अधिक प्रदुषण होता है

लोग पटाखों पर प्रतिबंध की मांग क्यों करते, महसूस किया जा सकता कि ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक प्रदूषण करते हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने के संबंध में कहा कि सिर्फ पटाखों से ही प्रदुषण नहीं होता है। कोर्ट ने पटाखों से होनेवाले प्रदुषण संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पटाखे ही प्रदुषण का एकमात्र कारण नहीं है। कार और ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक मात्रा में वातावरण को प्रदुषित करते है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख ३ अप्रैल की तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग पटाखों पर प्रतिबंध की मांग क्यों करते है जबकि साफ महसूस किया जा सकता है कि ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक प्रदूषण करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पटाखों के निर्माण में बेरियम का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जा चुका है। ग्रीन पटाखों का फार्म्युला अभी फाइनल किया जाना बाकी है। इश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बेरोजगार हुए कर्मचारियों का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वह पटाखों और ऑटोमोबाइल्स द्वारा होनेवाले प्रदुषण पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। रिपोर्ट में इस पर भी विचार किया जाए कि लोग ऑटोमोबाइल्स से प्रदुषण जानते हुए भी क्यों पटाखों पर बैन की मांग करते हैं जबकि ऑटोमोबाइल ज्यादा प्रदुषण फैलाता है। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए ३ अप्रैल की तारीख तय की गई है। बता दें कि पटाखों पर पिछले साल दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पुरी तरह से बैन लगाने से इनकार करते हुए कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते है। आपको बता दें कि वायु प्रदुषण पर लगाम के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस वक्त भी पटाखों पर लगे प्रतिबंधों के मामले पर काफी बवाल हुआ था।

राहुल गांधी का बीजेपी-आरएसएस पर तीखा हमला

अब तय करना है कि गांधी का हिंदुस्तान चाहिए या गोड्से का

कांग्रेस की सरकार बनने के साथ भारत रोजगार सृजन के मामले में चीन से स्पर्धा शुरू कर देगा : राहुल गांधी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और कहा कि अब लोगों को तय करना है कि उन्हें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए या फिर गोड्से का हिंदुस्तान चाहिए। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस लोकसभा चुनाव के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वह दिल्ली के बूथ लेवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा भारत चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, आप को तय करना है कि आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हैं या गोड्से का हिंदुस्तान चाहते है। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ नफरत है। राहुल गांधी ने दावा किया कि २०१९ में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हम निर्णय ले चुके हैं कि हम न्यूनतम आय गारंटी देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के साथ भारत रोजगार सृजन के मामले में चीन से स्पर्धा शुरू कर देगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस दिल्ली की सातों सीटों पर जीतेगी। इस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को एक तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलवामा हमले का जिक्र कर जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को १९९९ में केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा छोड़े जाने को लेकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा, पुलवामा में बम फटा। सीआरपीएफ के हमारे ४०-४५ लोग शहीद हुए। कांग्रेस की सरकार बनने के साथ भारत रोजगार सृजन के मामले में चीन से स्पर्धा शुरू कर देगा। अब यह ५६ इंच की छाती वाले, आपको याद होगा कि जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहरजी के साथ जो आज नैशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर हैं बम किसने फोड़ा, जैश-ए-मोहम्मद। मसूद अजहर याद होगा। बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा भारत चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, आप को तय करना है कि आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हैं या गोड्से का हिंदुस्तान चाहते है। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ नफरत है। राहुल गांधी ने दावा किया कि २०१९ में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हम निर्णय ले चुके हैं कि हम न्यूनतम आय गारंटी देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के साथ भारत रोजगार सृजन के मामले में चीन से स्पर्धा शुरू कर देगा। अब यह ५६ इंच की छाती वाले, आपको याद होगा कि जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहरजी के साथ जो आज नैशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर हैं अजीत डोभाल मसूद अजहर को जाकर कांधार में हवाले करके आ गए। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा, ५ साल पहले देश में एक चौकीदार आया और कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, मेरा ५६ इंच का सीना है। अब किसी से भी पूछ लीजिए चौकीदार क्या है तो वह बता देगा कि चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमाल है कि आप लोग देश के कोने-कोने में सच्चाई पहुंचा देते हो।

सारा अगली फिल्म लव आज कल २ में

सारा अली खान ने ठुकराई विकी कौशल की फिल्म ?

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

अपनी पहली ही फिल्म केदारनाथ से दर्शकों के दिलों में रच-बस चुकीं सारा अली खान लगातार खबरों में बनी हुई है। फिलहाल सारा अपनी अगली फिल्म लव आज कल २ की वजह से खबरों में है, लेकिन इसी के साथ सुनने में यह भी आ रहा है कि उन्होंने इसके लिए विकी कौशल की फिल्म ठुकरा दी। हालिया फिल्म सिंबा में रणवीर सिंह की शगुन बनकर सारा ने एक बार दर्शकों का दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि बॉलिवुड में वह लंबी पारी खेलने आई है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वह केवल दर्शकों की ही नहीं बल्कि फिल्म निर्देशकों की भी चहेती बन चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो सारा को विकी कौशल स्टारर शहीद उधम सिंह की बायॉपिक के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन के साथ अपनी फिल्म लव आज कल २ के लिए उन्होंने उस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। हालांकि, रिपोर्ट की मानें तो सारा का कहना है कि इस बायॉपिक में उनके लिए करने लायक कुछ भी क्रिएटिव नहीं था कि इस फिल्म को हां कहती। उनका कहना है कि बतौर ऐक्टर इस बायॉपिक में उन्हें कोई क्रिएटिव स्पेस नहीं मिलाता। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दोनों फिल्मों की डेट भी क्लैश हो रही थी, जिसके वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। खबरों की मानें तो इन्हीं वजहों से सारा ने टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी ३ में करने से इनकार कर दिया।

सारा अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वह केवल दर्शकों की ही नहीं बल्कि फिल्म निर्देशकों की भी चहेती

चुनाव के परिणाम बाद फिर कड़ी कार्रवाई

चुनाव का ऐलान होने पर अब सीलिंग अभियान पर रोक

टैक्स विभाग द्वारा डिफोल्टर्स की प्रॉपर्टी को सील करने कार्रवाई की गई : चुनाव को लेकर अभियान में नरमी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

देश की १७वीं लोकसभा चुनाव के लिए गत दिन से आचारसंहिता लागू करके इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जिसे लेकर देश के सभी राज्यों और शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में इसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होने की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम अनुसार गुजरात में आगामी २३ अप्रैल को मतदान आयोजित किया जाएगा। चुनाव की वजह से एक ओर राजनीति हलचल तेज हो गई है तो दूसरी तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स के डिफोल्टर्स को सीलिंग अभियान के कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। हालांकि, चुनाव के परिणाम बाद एएमसी प्रशासन द्वारा डिफोल्टर्स के विरूद्ध फिर से कड़ी कार्रवाई करने की संभावना है। एएमसी प्रशासन द्वारा शहरभर में सीलिंग अभियान के तहत ५० हजार रुपया या इसके ज्यादा बाकी प्रॉपर्टी टैक्स के डिफोल्टर्स की कॉमर्शियल संपत्तियों को सील किया जा रहा था। गत १ फरवरी, २०१९ से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान के तहत संपत्तियों को सील किया जाता था। टैक्स विभाग द्वारा डिफोल्टर्स की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से अब ठंड के दिनों में सुबह से डिफोल्टर्स अपनी प्रॉपर्टी की सील खुलवाने के लिए सक्रिय हो गये थे। गत १ फरवरी से गत ७ मार्च, २०१९ तक के टैक्स विभाग की सीलिंग अभियान के तहत आधिकारिक आंकड़े के अनुसार कुल १७,९८५ प्रॉपर्टी को सील किया गया था। यह सीलिंग अभियान से प्रशासन को ९६.५९ करोड़ रुपये की आय हुई थी। पश्चिम जोन में सबसे ज्यादा ३९३२ संपत्ति, उत्तर जोन में ३४८९ प्रॉपर्टी, दक्षिण जोन में २७०७ प्रॉपर्टी, मध्य जोन में २४७३ प्रॉपर्टी, उत्तर-पश्चिम जोन में २३५० प्रॉपर्टी दक्षिण पश्चिम जोन में १८९४प्रॉपर्टी और पूर्व जोन में सबसे कम ११६७ प्रॉपर्टी को सील किया गया था। उल्लेखनीय है कि, शासक पक्ष द्वारा पहले भी प्रशासन द्वारा सख्ती सीलिंग अभियान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था अब चुनाव का ऐलान होने के बाद शासकों द्वारा डिफोल्टर्स के खिलाफ नरमी से काम लेंगे।

हरएक विधानसभा प्रति सीट पांच सखी मतदान बनाये जाएंगे

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान केन्द्रीय चुनाव आयोग ने कर दिया है जिसकी वजह से गुजरात में चुनाव की शुरूआत हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में सिर्फ महिलाएं संचालित मतदान केंद्र सखी मतदान केंद्र को मिली सफलता बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव में अब हरएक विधानसभा प्रति सीट पांच सखी मतदान बनाये जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए प्रभावी कवायद शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अहमदाबाद में ६० सहित राज्यभर में कुल ९१० सखी मतदान बनाये जाएंगे। जिसमें पोलिंग से लेकर सुरक्षा तक का स्टाफ सिर्फ महिलाएं ही करेगी। यह सभी मतदान केंद्रों का संचालन सिर्फ महिलाएं ही करेगी। सखी मतदान केंद्र की पहचान के लिए मैरून रंग का अलग बोर्ड भी लगाया जाएगा। यह चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी प्रशासन ने मतदान कर सके ऐसी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा व्हील चेयर या वाहन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसके लिए दिव्यांग-विकलांग, बुजुर्ग मतदाताओं को पहले से ही योग्य व्यवस्था के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें कौन-से मतदान केन्द्र पर वह मतदान करने के लिए आयेंगे यह जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग ने आचारसंहिता के भंग सहित अन्य शिकायतों के लिए १९५० टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस पर मतदाता सूची, चुनाव संबंधी जानकारी, शिकायत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बार पहली बार ईवीएम में जीपीएस भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पोलिंग की ऑफिसर की कार में जीपीएस लगेगा।

४४.४८ करोड़ मतदाता दर्ज हुए

(संपूर्ण समाचार सेवा)अहमदाबाद,

गुजरात में लोकसभा की २६ सीटों के लिए २३ अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान गुजरात में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम का ऐलान करने के बाद गुजरात में मुख्य चुनाव अधिकारी एस. मुरलीकृष्ण ने कहा है कि आचारसंहिता लागू की गई है। गुजरात चुनाव का चित्र नीचे के अनुसार है।

कुल सीटें	२६
जनरल सीटें	२०
अनूसूचित जाति (आरक्षित)	२
अनूसूचित जनजाति (आरक्षित)	०४
कुल मतदाताओं की संख्या	४.४८ करोड़
पुरुष मतदाताओं की संख्या	२.३३ करोड़
महिला मतदाताओं की संख्या	२.१५ करोड़
पहचानपत्र रखनेवाले	४.४७ करोड़
पोलिंग स्टेशन	५१७०९
शहेरी क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन	१७३३०
ग्रामिण क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन	३४३७९
अध्यादेश जारी	२८ मार्च
उम्मीदवारी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख	४ अप्रैल
जांच की तारीख	५ अप्रैल
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख	८ अप्रैल
मतदान की तारीख	२३ अप्रैल
मत गिनती की तारीख	२३ मई

२०१४ में ६३ फीसदी मतदान

भूतकाल के परिणाम और मतदान प्रतिशत

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात में लोकसभा की २६ सीटों के लिए २३ अप्रैल को मतदान होगा और गुजरात में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भूतकाल में चुनाव के परिणाम और मतदान की प्रतिशत नीचे के अनुसार है।

वर्ष १९९८

पार्टी	कितनी सीटें
भाजपा	१९
कांग्रेस	०७

वर्ष १९९९

भाजपा	२०
कांग्रेस	०६

वर्ष २००४

भाजपा	१४
कांग्रेस	१२

वर्ष २००९

भाजपा	१५
कांग्रेस	११

वर्ष २०१४

भाजपा	२६
कांग्रेस	००

मतदान की प्रतिशत

वर्ष	मतदान प्रतिशत
१९९८	५९.३१
१९९९	४५.११
२००४	४५.१६
२००९	४७.८९
२०१४	६३.६६

भाजपा की मत हिस्सेदारी ज्यादा

मत हिस्सेदारी का चित्र

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात में लोकसभा की २६ सीटों के लिए २३ अप्रैल को मतदान होगा और गुजरात में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात में कौन से वर्ष में भाजपा और कांग्रेस की कितनी मत हिस्सेदारी रही यह नीचे के अनुसार है।

वर्ष १९९८

पार्टी	मत हिस्सेदारी (फीसदी में)
भाजपा	४८.२८
कांग्रेस	३६.४९
अन्य	१५.२३

वर्ष १९९९

भाजपा	५२.४८
कांग्रेस	४५.४४
अन्य	२.०८

वर्ष २००४

भाजप	४७.३७
कांग्रेस	४३.८६
अन्य	८.७७

वर्ष २००९

भाजप	४६.५२
कांग्रेस	४३.४८
अन्य	१०

वर्ष २०१४

भाजपा	५९.१
कांग्रेस	३२.९
अन्य	८

भाजपा हाईकमान द्वारा सूचना दी गई थी

भाजपा के कॉर्पोरेटरों ने एक से पांच लाख तक पार्टी फंड वसूला

भाजपा ने बचाव में कहा कि, यह फंड पंडित दीनदयाल समर्पणनिधि के तहत इस तरीके से वसूल किया जाता है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

विश्व की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी होने का दावा भाजपा कर रहा है। भाजपा पिछले पांच वर्ष से केंद्र-राज्य और शहर में सत्ता पर है यानी कि चुनावफंड के मामले में यह पार्टी स्वाभाविक रूप से धनिक है। हालांकि दो-तीन दिन पहले शहर की मेयर सहित के १४२ पार्टी के कॉर्पोरेटरों ने पार्टी चलाने के लिए नागरिकों से फंड योगदान जमा करके व्यक्तिगत रूप से १ लाख से पांच लाख रुपये तक की रकम पार्टी में जमा कराकर शहर भाजपा को लोकसभा चुनाव की मौसम में राहत पहुंचाई। हालांकि, भाजपा के कॉर्पोरेटरों द्वारा पार्टी फंड वसूलने का मुद्दा लोकसभा चुनाव का ऐलान होने की वजह से अब स्थानीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है।

शहर की मेयर बीजलबहन पटेल, स्टेन्डिंग कमेटी के चेयरमैन अमूल भट्ट और पार्टी नेता अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा की टीम गत अक्टूबर-२०१५ से सत्ता पर बिराजमान है। भाजपा की यह लगातार तीसरी टर्म होने

से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्टी के कुल १४२ कॉर्पोरेटर है। फिलहाल में मेयर बीजलबहन पटेल सहित के टोप के छह पदाधिकारी तथा स्पेशियल ११ कमेटी के चेयरमैन को भाजपा हाईकमान द्वारा जन योगदान में से पांच लाख रुपये और कॉर्पोरेटर को एक लाख जमा करने की सूचना दी गई थी। हालांकि कॉर्पोरेटर और पदाधिकारियों को फंड योगदान चेक से वसूलने की सूचना देकर संबंधित रकम वाली स्लीप दी गई थी। पिछले कई दिनों से निर्धारित रकम को जमा करने के लिए कॉर्पोरेटर मेहनत कर रहे थे। कॉर्पोरेटरों ने वसूली हुई रकम शहर भाजपा के महामंत्री और पूर्व वॉटर सप्लाय कमेटी के चेयरमैन को सौंपा गया है। हालांकि, इस मामले में शहर भाजपा के सूत्रों ने बचाव किया था कि, यह फंड योगदान जमा करने की बात लोकसभा चुनाव के साथ कोई लेनादेना नहीं है। पंडित दीनदयाल समर्पणनिधि के तहत हर दो वर्ष पर इसी तरीके से फंड वसूला जाता है।

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "GARVI GUJARAT" HINDI DAILY AS REQUIRED TO BE PUBLISHED UNDER RULE 8 OF REGISTRATION OF NEWS PAPER. (CENTRAL RULES 1856)

FORM - IV

(SEE RULE - 8)

1.	Place of Publication	TF-01,Nanakram Super Market,Rmanagar, Sabarmati, Ahmeabad- 380 005.
2.	Periodicity of its publication	Hindi Daily
3.	Printer's name	**AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	**Vansh Corporation,** A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
4.	Publisher's name	**AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI**
		131,Dharmanagar Society, Highway Road, Sabarmati, Ahmedabad- 380 005.
5.	Editor's name	**MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	48, Amarkunj Society, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad- 380 005.
6.	Owners Names And Address	**AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI** 131,Dharmanagar Society, Highway Road, Sabarmati, Ahmedabad- 380 005.

I **AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI** here by declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 12-03-2019

Ajaykumar Ramanlal Prajapati
Singaturs of Publisher.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पहला भाषण, पीएम मोदी पर निशाना साधा

(जी.एन.एस.) अहमदाबाद, कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को पहली बार गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित किया। गांधीनगर में करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी, प्रेम और अहिंसा की बात करते हुए भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह देश आपका है, जो लोग बड़ी–बड़ी बातें करते हैं उनसे पूछिए कि जो 15 लाख रुपये आपके खाते में आने थे, वे कहां हैं ? 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ ? उन्होंने कहा कि आने वाले दो महीनों में फिजूल के मुद्दे उठाए जाएंगे, ऐसे में आपको जागरूक होना है क्योंकि इस चुनाव के जरिए आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। गुजरात में करीब छह दशक बाद शाहीबाग सरदार पटेल स्मारक भवन में मंगलवार को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह व कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी के गढ़ गुजरात से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर नोटबंदी, जीएसटी व बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने गांधीनगर में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जागरूक बनें, यहीं देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल करना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह देश प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की नींव पर बना है। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, वह बहुत दुखद है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको सोचना होगा कि वास्तव में यह चुनाव क्या है। इस चुनाव में आप क्या चुनने जा रहे हैं ? आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। बेकार के मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए। जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए उनमें शामिल होना चाहिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनाव के मुद्दे हैं। गांधीनगर में कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात में अपनी पहली जनसभा में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव किसान, महिला व युवाओं के मुद्दों पर होना चाहिए। युवाओं को सवाल उठाने के साथ देश की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने देश के राजनीतिक माहौल को एक अलग मोड़ देते हुए कहा कि आगामी चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने किसी दल का नाम लिये बिना कहा कि वे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की फितरत ऐसी नहीं है। प्रियंका ने युवाओं से सही मुद्दें व सही सवाल उठाने की अपील करते हुए कहा कि ये देश आपका है। आप ही लोगों ने देश को बनाया। ये देश किसी एक का नहीं हो सकता। प्रियंका ने कहा कि पहली बार गुजरात आयी हूं। पहली बार उस आश्रम में गई, जहां से गांधीजी ने संघर्ष शुरू किया। यहां मेरे आंख में आसू आ गए । वहां बैठे मुझे याद आया देश आपसी प्यार से बना है। आज देश में जो हो रहा है। उससे बहुत दुख हो रहा है। सत्ता में आने पर गरीब पिछड़े और वंचितों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना लाएंगेः राहुल गांधीनगर में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव महात्मा गांधी व संघ की विचारधारा की लड़ाई के बीच होगा। राहुल ने कहा सत्ता में आने पर गरीब पिछड़े और वंचितों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना लाएंगे। गुजरात में करीब छह दशक बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को अनेक मुद्दों पर आड़े हाथ लिया। राहुल ने राफेल, बेरोजगारी, नोटबंदी व जीएसटी तथा किसानों की कर्ज माफी के मुद्दों को उठाया। राहुल ने सबसे पहले देश की अर्थ व्यवस्था को बदहाल करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये माफ कर दिए। लेकिन कांग्रेस ने तीन राज्यों में सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ किए। राहुल ने कहा जीएसटी को लागू करकने मोदी सरकार ने लघु व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। गुजरात जैसे उद्यमी राज्य की तो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डाली। राहुल ने एक बार फिर लोगों से पूछा कि 15 लाख उनके खाते में आये क्या। मोदी पर झूठ बोलने का आरोपल लगाते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल में कभी किसान की बात नहीं की। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश भक्ति की बात करते हैं। राफेल को लेकर वायुसेना सवाल उठाती है तो कोई जबाब नहीं देते। पाकिस्तान में जाकर बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान बनाने वाली एचएएल कंपनी को राफेल का ठेका नहीं देकर अपने मित्र अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया। राहुल ने कहा कि पुलवामा में जवानों पर हमला कराने वाले मसूद अजहर को भाजपा की वाजपेयी सरकार ही प्लेन में बैठाकर कंधार छोड़कर आई थी। वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उसी प्लेन में साथ गए थे। राहुल ने कहा कि मोदी देश को बताएं कि मसूद अजहर को भारत से ले जाकर पाकिस्तान की जमीन पर क्यों छोड़ आए। राहुल ने कहा कि भारत–पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था, तब प्रधानमंत्री ने देश के पांच हवाई अड्डे अपने दूसरे उद्यमी मित्र को दे दिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई साल बाद गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। हमने यहां बैठक आयोजित की, क्योंकि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है और गुजरात में आपको दोनों विचारधाराएं मिलेंगी। उनके मुताबिक, फासीवादी आरएसएस और उसकी विचारधारा को हराएंगे, कोई बलिदान की जरूरत नहीं। बहुत छोटा युद्ध है जीत जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो जीएसटी में बदलाव लाएंगे। देश की अर्थ व्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, परोक्ष रूप से मनमोहन सिंह ने जीएसटी व नोटबंदी के फैसले को गलत बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार झूठ फैलाती है, जनता को यूपीए सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत है। सोनिया ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया

वहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जान–बूझकर खुद को पीड़ित बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बीते पांच साल में देश की जनता पीड़ित है। सोनिया ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। पार्टी हित में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रहित में राजनीति होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि गलत नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, यूपीए सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताना जरूरी है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पीड़ित बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि मोदी शासन से जनता परेशान है। वहीं बीते पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो गई है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी आला नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने गांधी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद में आगंतुकों की किताब में लिखा है कि बहुत ही प्रेरणादायक जगह। हमारे नेता की लौ को जीवित रखने के लिए धन्यवाद। गांधी आश्रम में सोनिया गांधी ने आगंतुकों की पुस्तक में लिखा है कि इस संग्रहालय में जाना मेरे लिए सबसे अधिक प्रेरणादायक है ... हम उनसे (महात्मा गांधी), उनके जीवन, उनके बलिदान से प्रेरित हैं। गांधीनगर। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठ में पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रस्ताव में भाजपा पर देश मे विभाजन व नफरत की विचारधारा को फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में कहा कि महात्मा गांधी का 150 वां जंयति वर्ष है। गुजरात ने देश को गांधी व सरदार पटेल दिए। कांग्रेस ने गांधी सरदार व नेहरू के साथ स्वतंत्रता सैनानियों के बलिदान को भी याद किया। भारत विविध भाषा, संस्कृति व धर्म वाला देश है। देश के लोगों को भाईचारा में विश्वास है। लेकिन भाजपा व आरएसएस देश में हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो देश के लिए संघर्ष करने वाले व बलिदान देने वालों का अपमान है। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में परिपक्व लोकतंत्र है, जिसमें भिन्न मत विचारधार व दल का भी सम्मान किया जाता है। कार्यसमिति की बैठक से पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी सरदार पटेल स्मारक पहुंचे। हार्दिक ने पार्टी में शामिल होने से पहले यहां कहा कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से जुड़कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले हार्दिक् ने वयोवृद्ध पाटीदार नेता व पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल से आशीर्वाद लेने की इच्छा जताई लेकिन केशुभाई ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। गत दिनों लेउवा पटेल समाज की मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर आयोजित समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यहां केशुभाई को देखते ही उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पहले हार्दिक भी यादा कदा केशुभाई से मिलकर आशीर्वाद लेते रहे हैं लेकिन इस बार केशुभाई ने उनके कांग्रेस में शामिल होने के फैसले से नाराज होकर मिलने से ही इनकार कर दिया।

दिल्ली के किले में जीत का झंडा गाड़ेगे कोहली

दिल्ली में वनडे का आखिर में आज फाइनल मैच होगा

पटाखों से होनेवाले प्रदुषण संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा पटाखे ही प्रदुषण का एकमात्र कारण नहीं

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने के संबंध में कहा कि सिर्फ पटाखों से ही प्रदुषण नहीं होता है। कोर्ट ने पटाखों से होनेवाले प्रदुषण संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पटाखे ही प्रदुषण का एकमात्र कारण नहीं है। कार और ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक मात्रा में वातावरण को प्रदुषित करते है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख ३ अप्रैल की तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग पटाखों पर प्रतिबंध की मांग क्यों करते है जबकि साफ महसूस किया जा सकता है कि ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक प्रदूषण करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पटाखों के निर्माण में बेरियम का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जा चुका है। ग्रीन पटाखों का फार्म्युला अभी फाइनल किया जाना बाकी है। इश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बेरोजगार हुए कर्मचारियों का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वह पटाखों और ऑटोमोबाइल्स द्वारा होनेवाले प्रदुषण पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। रिपोर्ट में इस पर भी विचार किया जाए कि लोग ऑटोमोबाइल्स से प्रदुषण जानते हुए भी क्यों पटाखों पर बैन की मांग करते हैं जबकि ऑटोमोबाइल ज्यादा प्रदुषण फैलाता है। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए ३ अप्रैल की तारीख तय की गई है। बता दें कि पटाखों पर पिछले साल दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पुरी तरह से बैन लगाने से इनकार करते हुए कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते है। आपको बता दें कि वायु प्रदुषण पर लगाम के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस वक्त भी पटाखों पर लगे प्रतिबंधों के मामले पर काफी बवाल हुआ था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, आगामी लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए गुजरात में मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होगी।बैठक के बाद गांधीनगर के अडालज में एक रैली होगी जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आने के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। कांग्रेस की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात में ५८ साल बाद हो रही है। इससे पहले १९६१ में बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख अमित चावड़ा ने बताया कि सरदार पटेल स्मृति भवन में बैठक के बाद राहुल गांधी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने गांधी आश्रम जाएंगे । वहां पर तमाम नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वर्ष १९३० में यहां साबरमती आश्रम से १२ मार्च को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। वर्ष २०१९ को राष्ट्रपिता की १५० वीं जयंती के तौर पर भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह के गृह राज्य में आयोजित की जा रही रैली में कांग्रेस को तीन लाख लोगों के आने की संभावना है। एक महीने के भीतर राहुल गांधी का गुजरात का यह दूसरा दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने १४ फरवरी को वलसाड जिले में रैली को संबोधित किया था। वर्ष १९६१ में सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात के भावनगर में हुई थी। राहुल, मनमोहन व प्रियंका अडालज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज वे गांधीनगर अडालज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके करेंगे। गुजरात की वर्ष १९६० में स्थापना के बाद १९६१ में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक अहमदाबाद में हुई थी, उसके बाद पहली बार गुजरात में यह बैठक बुलाई गई है। पहले यह बैठक २८ फरवरी को होनी थी, लेकिन भारत व पाकिस्तान की सीमा पर उत्पन्न तनाव के माहौल को देखते हुए बैठक रद कर दी गई थी। कांग्रेस कार्यसमिति में शामिल कई राष्ट्रीय नेता ११ मार्च को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। राहुल गांधी, डॉ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी आदि नेता १२ मार्च को सुबह अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से सीधे गांधी आश्रम आएंगे। कांग्रेस ने दांडी मार्च की याद में यहां एक प्रार्थना सभा का आयोजन रखा है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी व पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी गुजरात से ही लोकसभा चुनाव प्रचार का श्रीगणेश करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा के मुताबिक, प्रार्थना सभा के बाद सरदार पटेल स्मारक भवन में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति व विविध मुद्दों पर चर्चा होगी । हाल ही में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले व इसके बाद भारत व पाकिस्तान के बीच पैदा हुए जंग के हालात पर भी कांग्रेस नेता चर्चा करेंगे । साथ ही, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों की कर्जमाफी, फसल बीमा, राफेल, महंगाई व बेरोजगारी, कांग्रेस छोड़ रहे विधायको के जैसे मुद्दों पर भी इस कार्यसमिति की बैठक में चर्चा होगी। अडालज त्रिमंदिर में एक जनसभा होगी, जिसे सभी बड़े नेता संबांधित करेंगे । प्रियंका गांधी गुजरात में पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश में पार्टी के पांच लाख सदस्य हैं, इनमें से शक्तिएप के जरिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

सैफ–सोनाली, तब्बू समेत ५ आरोपियों को नोटिस

(संपूर्ण समाचार सेवा) जोधपुर, राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई है। राज्य सरकार की याचिका पर इस मामले में बॉलिवुड ऐक्टर सैफ अली खान समेत पांच लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अभिनेता सलमान खान भी आरोपी हैं। राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी किया है। पिछले साल अभिनेता सलमान खान को वर्ष १९९८ में दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था और अप्रैल २०१८ में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी : सलमान भी आरोपी हैं यह घटना उस समय की है, जब सलमान खान और बाकी ऐक्टर्स राजस्थान में फिल्म हम साथ–साथ हैं की शूटिंग करने गए थे। सरकारी वकील के मुताबिक उस रात सारे कलाकार जिप्सी में सवार थे, जिसे सलमान खान चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकार मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। सबूतों के अभाव में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। अगस्त २०१८ में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया कि सलमान को विदेश जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। बता दें कि सलमान खान की ओर से विदेश जाने की परमिशन के लिए अपील दायर की गई थी।

२८ मार्च से उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे

गुजरात में ५१,७०९ बूथ पर २३ अप्रैल को मतदान

दो सीट अनुसूचित जाति, चार सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित : २० सीटें जनरल केटेगरी की

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात में लोकसभा की २६ सीटों के लिए २३ अप्रैल को मतदान होगा तब गुजरात में भी इसे लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान गुजरात में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित करने के बाद गुजरात में मुख्य चुनाव अधिकारी एस मुरलीकृष्ण ने कहा कि आचारसंहिता लागू हो गई है। उम्मीदवार २८ मार्च से लेकर ४ अप्रैल के दौरान सुबह में ११ बजे से लेकर तीन बजे तक उम्मीदवारी फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए दो सीट आरक्षित रखी गई है इसमें कच्छ और अहमदाबाद पश्चिम शामिल है जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई सीट में दाहोद, छोटाउदेपुर, बारडोली तथा वलसाड भी शामिल है। गुजरात में बाकी की २० सीटें जनरल केटेगरी में से उम्मीदवारों के लिए है । गुजरात में ५१७०९ मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा ही जिसमें से एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में और दो तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ८ मतदान केंद्रों पर १५०० से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाता है । ३८९५ मतदान केंद्रो पर ५०० से कम रजिस्टर्ड मतदाता है। ३१०५६ मतदान केंद्रों पर ५०० से १०० के बीच रजिस्टर्ड मतदाता है और १६७५० मतदान केंद्रों पर १००० और १५०० के बीच रजिस्टर्ड मतदाता है। गुजरात में २३ अप्रैल को मतदान आयोजित किया जाएगा । गुजरात में चुनाव के लिए अध्यादेश २८ मार्च को जारी किया जाएगा । उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख ४ से अप्रैल रहेगी। जांच की तारीख ५ अप्रैल रहेगी। उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख ८ अप्रैल होगी। सभी २६ सीट पर मतदान आयोजित किया जाएगा । लोकसभा चुनाव सात चरण में आयोजित किया जाएगा अब तीसरे चरण में गुजरात में चुनाव आयोजित किया जाएगा। चुनाव आयोग को यह दहशत सता रही है कि, गुजरात में चुनाव के दौरान मनी पावर का उपयोग हो सकता है । इस संभावना को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाये है। फ्लाइंग टीमें भी लगायी जाएंगी। चेकपोस्ट पर जांच की जाएगी। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी स्पर्धा होगी। गुजरात में २६ सीटों पर मत गिनती को लेकर सभी कदम उठाये गये हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH